

प्रेषक,

विजय कुमार ढौड़ियाल,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,  
सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग:-1

देहरादून,

दिनांक 11 फरवरी, 2016

**विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या:-2609/नियो/प्रशिक्षण/2015-16 दिनांक 04 फरवरी, 2016 एवं वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने विषयक वित्त विभाग के पत्र संख्या:-400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01 अप्रैल, 2015 व पत्र संख्या-645/XXVII (1)/2015 दिनांक 04 जून, 2015, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1136/XXVII(1)/2015 दिनांक 17 नवम्बर, 2015 के पैरा-5 के अनुसार एवं शासनादेश संख्या-1379/XXVII (1)/2015 दिनांक 27 नवम्बर, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राविधानित धनराशि में से अवशेष रु0 3,00,000/- (रूपये तीन लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) उक्त धनराशि का उपयोग प्रश्नगत सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों/मानकों के अनुसार ही किया जायेगा।

(2) निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड पर स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना महालेखाकार (लेखा) कार्यालय, उत्तराखण्ड को शासनादेश की प्रति के साथ तथा कोषागार का नाम व वाउचर संख्या, लेखाशीर्षक तथा आहरण की तिथि सहित सूचित करने का उत्तरदायित्व होगा।

(3) व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग के पत्र संख्या:-400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01 अप्रैल 2015 का व समय-समय पर निर्गत संगत आदेशों का अक्षरशः पालन निबन्धक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उच्ची मदों पर किया जाय जिसके लिये स्वीकृति दी जा रही है यदि उसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे तथा उन पर अनुशासनिक कार्यवाही करते हुये अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

(5) व्यय का योजनावार मासिक विवरण ठीक अगले माह की 5 तारीख तक बी0एम0-13 प्रपत्र पर नियमित रूप से वित्त विभाग, शासन तथा महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड को भिजवाना सुनिश्चित किया जाए।

(6) उक्त व्यय शासन के वर्तमान नियमों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय की उक्त धनराशि किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न की जाय जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित हो। प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता

(2)

नितान्त आवश्यक है अतः व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी जारी आदेशों तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

**2-** उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2425-सहकारिता-आयोजनागत-00-003-प्रशिक्षण-06-सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु अनुदान 00- की मानक मद 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

**3-** उपर्युक्त आदेश वित्त विभाग के पत्र सं-400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01अप्रैल, 2015, शासनादेश संख्या-1136/XXVII(1)/2015 दिनांक 17 नवम्बर, 2015 के पैरा-5 के अनुसार एवं शासनादेश संख्या-1379/XXVII(1)/2015 दिनांक 27 नवम्बर, 2015 तथा शासनादेश संख्या-49/XXVII(1)/2016 दिनांक 25 जनवरी, 2016 द्वारा दिए गए विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-आई0डी0 मूल में।

भवदीय,

(विजय कुमार ढौंडियाल)  
सचिव।

संख्या:-157 (1)/XIV-1/2015, तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. वित्त-4/नियोजन/भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा/देहरादून, उत्तराखण्ड।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
6. बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
7. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
8. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से  
(सुनील सिंह)  
उप सचिव।